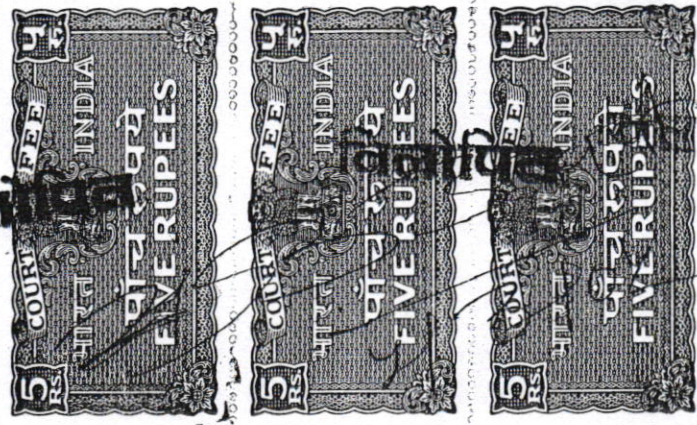


विलोपित



119/1

74

C-100/151-2

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म० प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12004 निगरानी

R 281- II/2005

श्री एस. के. अवस्थी-एडवोकेट
द्वारा आज दि० 5/3/05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

5 MAR 2005

2005/3/28
21/3/05

- १। राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्रीकृष्ण शर्मा
- २। रामलखन पुत्र विद्याराम शर्मा
निवासीगण ग्राम खुटियानी हार
तहसील जौरा, जिला मुरैना। म० प्र०
-- प्राथीगण

विद्द

- १। राधेश्याम २। रामवरन पुत्रगण
श्री अमृतलाल
- ३। बृजमोहन पुत्र अमृतलाल नावालिग
सुरेन्द्राक माई स्वयं राधेश्याम पुत्र
श्री अमृतलाल
- ४। मुन्नोबाई पत्नी श्री ओमप्रकाश सरपंच
खुटियानी हार
सभी निवासीगण ग्राम खुटियानी हार
तहसील जौरा, जिला मुरैना, म० प्र०
-- प्रतिप्राथीगण

निगरानी विद्द आदेश आयुक्त महोदय, वम्बल संभाग, मुरैना
दिनांक २४-०१-२००५ अन्तर्गत धारा ५० म० प्र० मुराजस्व संहिता,
१९५६। प्रकरण क्रमांक १११/२००३-२००४ निगरानी।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- (१) यहकि आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।
- (२) यहकि आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।
- (३) यहकि यदि आयुक्त महोदय ने सही समझा होता तो प्रकरण को सही तरीके से निगरानी देते।

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 281-दो/2005

जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28-11-2016	<p>आवेदक अभिभाषक श्री डी०के० दीक्षित उपस्थित।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि इस प्रकरण में पूर्व से व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है इसलिए उक्त आदेश के तारतम्य में प्रकरण का निराकरण किया जाये।</p> <p>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 27-7-2004 को आवेदकगण की निगरानी को आंशिक रूप से सहमत होते हुये तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जौरा जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक अपील 1/2011 में दिनांक 14-8-2012 को निर्णय पारित किया गया है। व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। आवेदक तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। व्यवहार न्यायालय के आदेश के क्रम में अग्रिम कार्यवाही की जाना है इसलिए इस न्यायालय से किसी प्रकार के निष्कर्ष निकाला जाना उचित न होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(एस०एस० अली) सदस्य</p>	